during the IV Plan. The number of new major/medium Schemes approved/ cleared so far during the Fifth Plan is 235.

Irrigation is a State Subject and irrigation schemes are planned, and executed by the State Governments within their developmental Plans. In addition, minor schemes are also executed by the Panchayats and individuals. Minor Schemes generally require small outlays and are completed within 1—3 years. Major and Medium Schemes require large outlays and the programmes for their construction generally depand on the availability of funds, labour, construction material, land acquisition with consequential rehabilitation problems geology of the foundations of various structures etc. The schedules for their construction are, therefore, revised frequently depending on these factors and it is difficult to pin-point original schedule dates of completion. In case of most of the major projects started during the Fourth Plan period it was originally stipulated that these would be completed by the end of the Fifth Plan. On many of these projects the completion is likely to be delayed. As per present assessment, four of the major schemes started in the Fourth Plan period are expected to be completed by the end of the current Plan. In case of new schemes taken up during the Fifth Plan period so far, it is too early to predict whether there would be delay in their execution or not.

(d) The main reasons for delay in construction have been the non-availability of requisite funds and other necessary inputs resulting in long gestation period during which prices rise; inadequate investigations, change in scope and design during execution, land acquisition and rehabilitation problems etc.

Cashewnut area of Kandarkottai

5560. SHRI V. S. EIANCHEZHIAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the importance of Kandarkottai in Pudukotiah district as a cashewnut producing area;

(b) whether Government have proposals to promote, foster and encourage cashewnut processing industries in that area so as to utilise the considerable production of cashewnut and also to generate employment opportunities; and

(c) if so, the particulars in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir. Cashew is grown in Kandarkottai area of Pudukottai district.

(b) Government have no proposal nor are they contemplating any increase in the processing industry, since there is already a very big gap between the installed processing capacity of cashewnuts and the availability of rawnuts for processing in the country.

(c) Does not arise.

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

5561. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं और उन में से उनके द्वारा अधिकृत की गई कालोनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन कालोनियों में, जिन्हें अधिकृत किया जा रहा है, मकान बनाने वाले निवासियों से सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रस्तावित शुल्क क्या हैं और कहां पर पानी तथा बस

की सुविधा कब तक दी जाएगी ; तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था कब तक की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने काफी दूर के क्षेत्रों में बसाए गए इन झुग्गी निवासियों को अच्छी बस सुविधा दी है ताकि वे सुबह और शाम अपने काम पर आ जा सकें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बसाये गए इन सभी व्यक्तियों के पास प्लाट की पर्चियां थीं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन के पास प्लाट की पर्चियां थीं लेकिन उन्हें अलाटमेंट नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं तथा इसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) दो सूचियां, दिल्ली में अनअनुमोदित कालोनियों की एक सूची तथा अनुमोदित कालोनियों की दूसरी सूची इसके साथ सभा पटल पर रख दी गयी है । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी 881/77]**

(ख) नियमित की जाने वाला कालोनियों में जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं उनसे वसूल किये जाने वाले प्रभार अभी तक निर्धारित नहीं किये गए हैं

32 अनधिकृत कालोनियों में पानी के नल (वाटर मेन्ज) लगाये जा चुके हैं ।

जहां तक बसों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों और हस्पतालों की सुविधा का संबंध है, डी० टी० सी० तथा दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है क्योंकि इन मामलों का उन्हीं से संबंध है । इन सभी बस्तियों में, पानी, बस, स्कूल तथा हस्पताल की सुविधायें कब तक दे दी जायेंगी इसके लिये इस समय कोई समयसीमा नहीं बताई जा सकती ।

(ग) डी० टी० सी० से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जिन लोगों को इमारत गिराने की पर्चियां दे दी थीं उन्हें सफाई की कार्रवाई के दौरान उसी समय पुनर्वास कालोनियों में प्लाट आवंटित कर दिये गये थे । जिन लोगों ने आवंटन के प्रस्ताव अथवा पुनर्वास कालोनियों के अन्य किसी स्थान पर वैकल्पिक प्लाटों के प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया तथा इमारतों को गिराने की पर्चियों को अपने ही पास रख लिया उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । फिर भी, जब कभी कुछ लोग जिनके पास इमारतों को गिराने की पर्चियां होती है, उन्हें प्रस्तुत करता है तो उन लोगों को उन पुनर्वास कालोनियों में जिनमें प्लाट उपलब्ध हैं स्थान दे दिया जाता है ।

Stock Problem of Rice and Sugar

5562. SHRI HOPINGSTONE LYNGDOH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the stock position of rice and sugar at the Central Godown ready for distribution to the different States as on the 30th June, 1977;

(b) the stock position at the Shillong godown as on 30th June, 1977; and

(c) whether it is a fact that substandard rice and sugar were sent to Meghalaya?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The stock held by the Food Corporation of India on Central Account as on 30th June, 1977 was about 37.85 lakh tonnes of rice and about 1.5 lakh tonnes of sugar.

(b) The stock at Shillong godowns as on 30th June, 1977 was 850 tonnes of rice and 87 tonnes of sugar.

(c) No, Sir.